विकास संघर्ष समिति के नाम पर शुरु होने वाले एक और सलवा जुडुम के खिलाफ आवाज बुलंद करो!

जनता एवं जनवादियों, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, लेखकों, शिक्षकों,
वकीलों, मीडिया कर्मियों, मानवाधिकार संगठनों, आदिवासी,
गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, सर्व आदिवासी समाज व सर्व समाज से अपील

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

विकास संघर्ष समिति के नाम पर शुरु होने वाले

एक और सलवा जुडुम के खिलाफ आवाज बुलंद करो!

जनता एवं जनवादियों, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, लेखकों, शिक्षकों, वकीलों, मीडिया कर्मियों, मानवाधिकार संगठनों, आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, सर्व आदिवासी समाज व सर्व समाज से अपील

अब तक आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हो गये होंगे कि झीरम घाटी में पीएलजीए के हाथों मारे गये जन दुश्मन व लुटेरे शासक वर्गों के अव्वल नंबर का दलाल महेंद्र कर्मा के बेटे छवींद्र कर्मा और चैतराम अट्टामी, पी. विजय, सत्तार अली जैसे सलवा जुडुम के जीवित बचे गैंग लीडरों व भाजपा के गुण्डों द्वारा बस्तर में 'शांति' और 'विकास' के लिए विकास संघर्ष समिति के नाम पर सलवा जुडुम–2 शुरु करने की 5 मई को घोषणा की गई। हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार के संरक्षण में कांग्रेसी कर्मा परिवार एवं भाजपाई गुण्डों व जन विरोधी मुखियाओं का संगठित हत्यारा–गुण्डा गिरोह है, यह विकास संघर्ष समिति। यह दरअसल वर्तमान पाशविक सैनिक दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट को तेज करने के लिए ही है।

एक और सलवा जुडुम क्यों ?

'शांति' और 'विकास' के नाम पर सलवा जुडुम–2 का मतलब है, राज्य की प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों को देशी–विदेशी पूंजीपति घरानों के हवाले करना एवं स्वयं शासन व सही विकास की राह में दण्डकारण्य में नवोदित जन राजसत्ता के अंग–क्रांतिकारी जनता ना सरकारों के उन्मूलन के लिए जनता पर जारी फासीवादी सैनिक–सांगठनिक दमन अभियान ग्रीनहंट को तेज करना।

संसाधन बहुल दण्डकारण्य इलाके में टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, निको आदि दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों एवं टीपीजी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पूंजी निवेश का रास्ता सुगम बनाना ही इसका असली उद्देश्य है। इन कंपनियों के साथ लाखों करोड़ रुपये के एमओयु किये गये हैं। सिर्फ टाटा, एस्सार के साथ ही इस्पात संयंत्रों के लिए 17 हजार करोड़ के एमओयु किये गये हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन कॉरपोरेट घरानों के लिए करीबन एक लाख एकड़ जमीन जिसका अधिकांश हिस्सा आदिवासियों की है, जबरन अधिग्रहित करने की कवायद जारी है। संविधान की पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों से उन्हें वंचित करते हुए यह सब किया जा रहा है। बस्तर संभाग के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थित रावघाट, चारगांव, बरबसपुर, कुव्वे, बुधियारी माड, आमदाई, तुलाड एवं राजनांदगांव स्थित पल्लेमाड सहित करीबन दो दर्जन से भी ज्यादा लौह अयस्क खदानों एवं गढ़चिरोली स्थित सुरजागढ़ सहित कइयों खदानों को देशी, विदेशी पूंजीपतियों को लीज पर दिया गया है। साथ ही टाटा, एस्सार एवं अन्य कंपनियों व एनएमडीसी के साथ वृहद् इस्पात संयंत्र लगाने के एमओयु किये गये हैं। संसाधनों की सस्ती लूट एवं सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन का जबरन निर्माण किया जा रहा है। नारायणपुर जिले के माड जो कि सदियों से प्राचीनतम आदिवासी जनजातियों में से एक माडिया जनजाति का निवास स्थान है, के एक चौथाई हिस्से पर सैनिक प्रशिक्षण शाला के नाम पर सैनिक अड्डा बनाने की योजना पर अमल हो रहा है। इन तमाम परियोजनाओं के खिलाफ जन आन्दोलन जारी हैं। इन परियोजनाओं को शुरु करने के लिए ही राज्य पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्ध–सैनिक बलों जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी शामिल हैं, के दर्जनों थानें व कैंप बिठाये गये हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है। इन थानों व कैंपों से गश्त के नाम पर फोर्स द्वारा गांवों पर लगातार हमलें जारी हैं। फर्जी मुठभेड़ें, नरसंहार, अंधाधुंध गिरफ्तारियां संघर्ष इलाकों में आम बात बन गयी है। इन इलाकों में दमन का प्रतिरोध करते हुए विस्थापन विरोधी जन संघर्ष तेज हो रहे हैं। केंद्र सरकार के हाल के भू अधिग्रहण कानून के खिलाफ भी यहां की जनता आन्दोलन की राह पर अग्रसर है। देशी, विदेशी कॉररपोरेट घरानों के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के दंतेवाडा दौरे के ऐन पहले सलवा जुडुम की घोषण को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।

शासक वर्गों की शांति और विकास का मतलब क्या है ?

शोषक–शासक वर्गों की शांति का मतलब है, जनता पर जारी हिंसा, लूट–पाट, अत्याचार एवं जनता के शोषण, दमन को बिना सवाल किये चुप–चाप सहना। सवाल करने पर शांति भंग हो जाती है। सवाल करने वाले, विरोध में आवाज उठाने वाले उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी या माओवादी हो जाते हैं और उन्हें शिकार किया जाता है। उनकी शांति का मतलब ही हिंसा है। संघर्षरत जनता को चुप कराना ही उनकी शांति है। पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए आम जनता को भूख, गरीबी, बेइज्जती, मौत का शिकार बनाया जाता है।

लुटेरी सरकारों के विकास का मतलब है–सामंतवादियों, दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों का विकास, नेताओं व अफसरशाहों का विकास। विकास का मतलब वृहत् उद्योग, बड़ी खनन परियोजनाएं, बडे बांध, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक गलियारें, परमाणु संयंत्र, वायु सैनिक व सैनिक अड्डें, सैनिक प्रशिक्षण शालाएं, चौड़ी–चमचमाती सड़कें, सूपर हाईवेज, पंच सितारा होटलें, आसमान छूती महलें, मोबाइल टावर, कॉरपोरेट बैंकें एवं पुलिस थानें व कैंप ही हैं।

विकास का मतलब है, जनता के जल–जंगल–जमीन व खनिज संसाधनों को हड़पना। उनके विकास का मतलब है, पर्यावरण का विध्वंस। पूंजीपतियों के मुनाफे के लालच में संसाधनों के अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। रावघाट को ही लीजिए, मानसूनी बारिश के लिए रावघाट पहाड पूरे एशिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पहाडी श्रृंखला के खनन से बस्तर में मानसूनी बारिश बुरी तरह प्रभावित होगी। बैलाडीला खनन परियोजना से बस्तर की आम जानता का कितना विनाश हुआ यह जग जाहिर है। बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक बिछी एस्सार की पाइप लाइन से बस्तर के भूजल स्तर के घटने की बात किसी से छुपी नहीं है। यह परियोजना सिर्फ एस्सार कंपनी की लौह अयस्क ढुलाई की दर को रेल गाडी द्वारा 300 रु. प्रति टन की जगह पाइप लाइन द्वारा 50 रु. प्रति टन करने के लिए ही है। बैलाडीला में लौह अयस्क की धुलाई से मलिंगेर नदी इस कदर प्रदूषित है कि इनसान तो क्या, जानवर एवं पशु–पक्षियों के पीने या अन्य इस्तेमाल के लायक भी नहीं रहा। बैलाडीला के लाल पानी से प्रभावित जनता संघर्ष की राह पर डटी हुई है। रावघाट परियोजना से मेंढकी नदी का भी वही हाल होनेवाला है। कुलमिलाकर जनता का विस्थापन एवं जन जीवन को तहस–नहस करना ही उनका विकास है।

जनता के असली विकास का मतलब है, देश की बहुसंख्यक जनता को खाना, पानी, कपडा, मकान, जमीन, शिक्षा, इलाज, रोजगार, सिंचाई आदि मूलभूत सुविधाओं से लैस करना। लेकिन लुटेरी सरकारों को आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। उनकी समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। जनता को क्रांतिकारी आन्दोलन से भटकाने, दूर करने व एक छोटे तबके को अपनी ओर आकर्षित करने की गलत नीयत से ये सरकारें संघर्ष इलाकों में झूठी सुधार योजनाओं पर अमल कर रही हैं। देशी, विदेशी पूंजीपति घरानों व दमनकारी राज्य यंत्र के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जैसे सड़कें, मोबाइल टावर, पुलिस कैंप, रेल लाइन, बांध आदि के लिए हजारों करोड़ जन धन खर्च कर रही हैं। जबकि राज्य की आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट की बहुत कम ही राशि खर्च की जाती है। वह भी ऊपर से नीचे यानी गांव तक पहुंचते–पहुंचते एक चौथाई से भी कम हो जाती है। एक आंकलन के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य से हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग अपने बूढ़ों व बच्चों को छोड़कर आजीविका की तलाश में दर–दर भटकते हुए पलायन कर जाते हैं और लूट व अत्याचारों के शिकार हो जाते हैं। सरकारों के बहुप्रचारित मनरेगा हो या कोई और योजना इस पलायन को रोक पाने में नाकाम हैं। किसानों की आत्महत्याओं के मामले में छग किसी दूसरे राज्य से पीछे नहीं है। शिक्षकों सहित तमाम कर्मचारी अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकारें लाठी, जेल,गोली को ही समस्याओं के एकमात्र समाधान के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली लुटेरी सरकारों से जनता के असली विकास की आशा नहीं की जा सकती है।

सरकारी सशस्त्र बलों के आतंकी व दरिंदे चेहरे पर परदा डालने की नाकाम कोशिश के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किये जा रहे हैं। जनता के खून से सने सशस्त्र बलों के हाथों सामान बंटवाये जा रहे हैं। इसलिए सलवा जुडुम न शांति अभियान है और न ही वह विकास के लिए है।

यह है शासक वर्गों की शांति का मतलब

यह है शासक वर्गों द्वरा हो रहा विकास

ये हैं राहत देनेवाले शिविर

दमन दण्डकारण्य की जनता के लिए नया नहीं

विगत 35 सालों के बस्तर के क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास में यहां की संघर्षरत जनता कई दमन अभियानों को झेल चुकी है। साहस के साथ उनका मुकाबला करके, उन्हें परास्त करने के अनुभव से भी वह लैस है।

जन जागरण के नाम पर जन दमन अभियानः सन् 1990–91 के पहले 'जन जागरण' के गुण्डों के द्वारा जन संगठनों के कई कार्यकर्ताओं व नेताओं की निर्मम हत्या की गयी एवं सैकडों की बेरहमी से पिटीई की गयी। दसियों महिलाओं का बलात्कार किया गया था। पार्टी के नेतृत्व में संघर्षरत जनता ने उक्त जन दमन अभियान को परास्त किया था। फिर 1997–98 के दूसरे 'जन जागरण' अभियान को भी पार्टी के नेतृत्व में बस्तर की लड़ाकू जनता ने बहुत कम समय में ही परास्त किया था।

सलवा जुडुम–क्या शांति व विकास का अभियान था?

सलवा जुडुम न ही शांति अभियान था और न ही उसे जनता के विकास से कोई लेना–देना है। असली शांति एवं असली विकास के लड़ने वाली जनता का दमन करने के लिए उद्देश्यित व केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा संचालित फासीवादी सैनिक, सांगठनिक दमन अभियान था, सलवा जुडुम। जून, 2005 में प्रारंभ होकर चार साल तक संचालित सलवा जुडुम के लिए सीआरपीएफ के अलावा नगा व मिजो बटालियनों को भी तैनात किया गया था। शाला भवनों को सशस्त्र बलों के अड्डे बनाये गये थे। इस दौरान सरकारी सशस्त्र बलों व सलवा जुडुम के गुण्डा गिरोह के पाशविक हमलों में 700 गांव तबाह हो गये। पंद्रह सै से ज्यादा आदिवासियों जिनमें दो साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बूढ़ों तक शामिल हैं, की बर्बर तरीके से हत्या की गयी। दर्जनों नरसंहार किये गये। सैकडों को अवैध रूप से गिरफ्तार करके झूठे केसों में फंसाकर जेलों में ठूंस दिया गया था। झूठी गवाही पर कइयों को लंबी व उम्र कैद की सजाएं दी गयी। सैकडों युवतियों व महिलाओं का बलात्कार किया गया। कइयों की सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या की गयी। महिलाओं की छातियां काट दी गयी, गर्भवति महिलाओं की हत्या के बाद पेट फाडकर भ्रूण को दीवार पर टंगा दिया गया था। सलवा जुडुम की जघन्य व नीच कारनामों को सुनकर सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जायेगा। सैकडों करोडों की चल व अचल संपत्ति लूट ली गयी या जलाकर नष्ट कर दी गयी। आदिवासी युवाओं को लालच देकर, डरा–धमकाकर, आतंकित करके उनमें से हजारों को एसपीओ बनाये गये। अपनी ही उंगली से अपनी आंखें फोडवाने व सामाजिक विभाजन की साजिश थी, यह।

जन आन्दोलन व जन युद्ध को खत्म करने के लक्ष्य से राहत शिविरों के नाम से बंदी शिविरों को बनाया गया था। गांवों पर लगातार हमलें करके 80 हजार से भी ज्यादा लोगों को गाय, बैलों की तरह लोगों को हांककर उन शिविरों में ले जाया गया था जहां उनका जीवन जेलों के बंदी जीवन से भी बदतर थी। जुडुम गुण्डों व सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं पर यौन अत्याचार व उत्पीडन असहनीय था एवं आम बात बन गयी थी। पार्टी व जनवादियों के लगातार प्रयास से यातनाभरित बंदी जीवन से त्रस्त लोग बंदी शिविरों से अपने गांवों में लौट गये। इतना ही नहीं, करीबन एक लाख से भी ज्यादा लोग सरकारी सशस्त्र बलों के हमलों, नरसंहारों, फर्जी मुठभेडों, अत्याचारों व यातनाओं से डरकर अपना सब कुछ छोड़कर तेलंगाण, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में पलायन कर गये हैं जहां वे विस्थापित जीवन बिता रहे हैं। सलवा जुडुम के हमलों में करीबन एक लाख लोग बेघर होकर जंगलों में भटकते हुए, जीवन–मरण का संघर्ष करते रहे। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि सलवा जुडुम की सरल व्याख्या करते हुए छग के एक बुद्धिजीवी ने यह कहा कि 25 साल के माओवादी आन्दोलन में एक भी आदिवासी का घर नहीं जला जबकि 4 साल के सलवा जुडुम ने दसियों हजार घरों को जलाया और लाखों को बेघर किया। यहां यह गौर करने वाली बात है कि इस आतंकी सलवा जुडुम को जनता का स्वस्फूर्त व शांति अभियान के रूप में प्रचारित किया गया था। इससे यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा कि सलवा जुडुम कितना शांतिपूर्ण था और होगा।

मजबूत जन आन्दोलन व जनयुद्ध को तेज करने के जरिए इसका डटकर मुकाबला किया गया था। देश–दुनिया की प्रगतिशील व जनवादी सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, शिक्षकों, वकीलों, मीडिया कर्मियों ने सलवा जुडुम फासीवादी सैनिक–सांगठनिक दमन अभियान के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद की, सड़क पर उतर आये व कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः सरकार को सलवा जुडुम बंद करना पडा।

ऑपरेशन ग्रीनहंटः अगस्त, 2009 से प्रारंभ देशव्यापी फासीवादी सैनिक दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत पूरे संघर्ष इलाकें में कॉरपेट सिक्युरिटी का जाल बिछा रहे हैं। पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों के दसियों बटालियन तैनात करके सैकडों कैंप–थानें बिठाये जा रहे हैं। गांवों पर हमलें रोजमर्रे की बात हो गयी है। दिवालिया आत्मसमर्पण नीति पर जोर लगा रहे हैं। एड्समेट्टा, सारकेनगुडा जैसे नरसंहारों द्वारा जनता को आतंकित करने की साजिश चल रही है।

ऑपरेशन ग्रीनहंट का पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए, जनता ना सरकारें, जन संगठन व जनता अनगिनत कुरबानियां देते हुए साहस के साथ मुकाबला कर रही हैं। इसे जनता पर युद्ध की संज्ञा देकर देश–दुनिया के सर्वहारा वर्गीय संगठन, माओवादी पार्टियां व संगठन, मानवाधिकार संगठन, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील–जनवादी ताकतें व मीडिया इस पाशविक दमन अभियान के खिलाफ एवं भारत में जारी जनयुद्ध के समर्थन में अभूतपूर्व ढ़ंग से आगे आ रही हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह आगे भी न केवल जारी रहेगा, बल्कि और मजबूत होगा।

टाटा, एस्सार द्वारा प्रायोजितः यहां यह गौर करने वाली बात है कि सलवा जुडुम व बंदी शिविरों के संचालन के लिए टाटा एवं एस्सार कंपनियों के सीएसआर–कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की मद् से करोड़ों की राशि आबंटित की गयी थी। इन कंपनियों के पक्ष में प्रचार करने व जनता को जबरन राजी करने जन विरोधी रहे तत्कालीन विपक्षी नेता महेंद्र कर्मा और सत्ता पक्ष के सांसद बलीराम कश्यप सरीके लोगों को मोटी रकम दी गयी थी। बेशक, अब भी ये कंपनियां अपनी परियोजनाओं को शीघ्र शुरु करने की कवायद के तहत विकास संघर्ष समिति के नाम पर फिर से सलवा जुडुम को प्रायोजित कर रही हैं। हाल ही में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित इस कथन की ओर ध्यान आकृष्ट करना यहां लाजिमी होगा कि एस्सार ने सीनियर आईपीएस गिरिधारी नायक जिनके बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि वह समीप भविष्य में राज्य के डीजीपी बनने वाले है एवं सीनियर आईएएस दुर्गेश मिश्रा जिनके बारे में उद्योग सचिव बनने का पूर्वानुमान लगाया गया है, पर डोरे डाले हुए है। उन्हें लाखों से नवाजे जाने की भी खबर है। इससे कॉरपोरेट कंपनियों की कार्यशैली का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। टाटा, एस्सार, निको, जिंदल, मित्तल, टीपीजी आदि देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की बडी खनन व बडे कारखानों से संबंधित तमाम परियोजनाओं के खिलाफ यानी अपने विस्थापन के खिलाफ संघर्षों को तेज करके ही जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाया जा सकता है।

अपीलः हमारी पार्टी दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता का आह्वान करती है कि वह पहले के दो जन जागरण व सलवा जुडुम को हराने के अपने विगत के अनुभवों व सीख के आधार पर वर्तमान सलवा जुडुम का डटकर मुकाबला करके उसे परास्त करे।

चूंकि यह अभियान बस्तरिया आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है इसलिए इस जन विरोधी अभियान से न सिर्फ दूर रहने, बल्कि इसके खिलाफ मजबूती से खडे होने हम आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, सर्व आदिवासी समाज व सर्व समाज से अपील करते हैं।

राज्य एवं देश–दुनिया की प्रगतिशील व जनवादी मानवाधिकार संगठनों व सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों, शिक्षकों, वकीलों, मीडिया कर्मियों से हम अपील करते हैं कि वे इस जन दमनकारी व विनाशकारी फासीवादी सांगठनिक अभियान के विरोध में सड़क पर उतरें, आवाज बुलंद करें एवं जनता के जल–जंगल–जमीन, संसाधनों, आदिवासी अस्तित्व व अस्मिता को बचाये रखने आगे आवें।

अब फिर एक बार शांति एवं विकास के नाम पर सलवा जुडुम का आतंक व जुल्म शुरु होने वाला है जिसे परास्त करके ही बस्तर के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। जन युद्ध व जन आन्दोलन को तेज करके दमन अभियानों को परास्त कर सकते हैं और तद्वारा जन राजसत्ता के अंग–क्रांतिकारी जनता ना सरकारों को मजबूत कर सकते हैं तथा उनका विस्तार कर सकते हैं। तभी असली मायने में दण्डकारण्य जनता का स्वयं शासन सही विकास संभव है।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)